झारखण्ड सरकार

मुख्यमंत्री सचिवालय

प्रेस विज्ञप्ति

राँची,दिनांक–14.03.2018

- **समर्पण और सेवा भाव से लक्ष्य को पूरा करें।**
- **2 अक्टूबर 2015 से चल रही उज्ज्वला योजना के तहत बचे हुए 15 लाख लाभुकों को अप्रैल माह तक गैस कनेक्सन देने की कार्रवाई करें।**
- **कैम्प लगाकर ही एलपीजी कनेक्सन वितरित किये जाएं।**
- **गरीबों की योजना में भ्रष्टाचार करने वाले नपेंगे।**
- **डीलर 20 सूत्री प्रखण्ड उपाध्यक्ष के साथ समन्वय बनाकर काम करेंगे।**

-रघुवर दास, मुख्यमंत्री

उज्जवला योजना के प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने जिला एवं प्रखण्डस्तरीय 20 सूत्री समिति को बड़ा लक्ष्य दिया । उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर 2015 से चल रही प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अंतर्गत **अप्रैल 2018 तक राज्य के बचे हुए 15 लाख लाभुकों तक अभियान चलाकर एलपीजी गैस कनेक्शन एवं चुल्हा उपलब्ध कराएं।** मुख्यमंत्री ने एक रोडमैप देते हुए बताया कि **राज्य 20 सूत्री उपाध्यक्ष प्रत्येक 15 दिन पर जिला 20 सूत्री के कार्यों की गहन समीक्षा करें तथा जिला 20 सूत्री उपाध्यक्ष हर 15 दिन पर प्रखण्ड 20 सूत्री उपाध्यक्षों के कार्यों की प्रगति की समीक्षा करें।** रांची के रिम्स ऑडिटोरियम में राज्य 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत आयोजित प्रधानमंत्री उज्जवला योजना की समीक्षात्मक बैठक में मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि **गरीबों की योजनाओं में जो भ्रष्टाचार करेगा वह सीधे नप जाएगा। काम नहीं करने वालों को पदमुक्त भी किया जाएगा। उन्होंने खाद्य आपूर्ति विभाग को निदेश दिया कि विभाग द्वारा तैयार लाभुकों की सूची अगले तीन दिन के अन्दर जिला आपूर्ति पदाधिकारी के माध्यम से सभी 20 सूत्री प्रखण्ड उपाध्यक्षों को उपलब्ध करायी जाए।** मुख्यमंत्री ने पलामू जिला 20 सूत्री की टीम को 74 प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के लिए बधाई देते हुए कहा कि सभी जिला इसी अनुरूप कार्य करते हुए अप्रैल तक उज्जवला योजना के लक्ष्य को पूरा करें

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी गैस डीलर 20 सूत्री प्रखण्ड उपाध्यक्षों के साथ समन्वय बनाकर सहयोग देते हुए काम करेंगे। कहीं से भी आपसी तालमेल टूटने की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। मुख्यमत्री ने कहा कि एलपीजी कनेक्सन और चुल्हा का वितरण कैम्प लगाकर ही करें। जिला प्रशासन लाभुकों को कैम्प तक लाना सुनिश्चित करें। पूरे राज्य में कहीं से भी सीधे वितरण की शिकायत नहीं आनी चाहिए। गैस कंपनियों के द्वारा 312 नये एलपीजी डीलर के लिए कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री ने गैस कम्पनियों के राज्य प्रतिनिधियों को यह निदेश दिया अगले 2 माह के अन्दर ये बहाल कर दिये जाए। वर्तमान डीलरों के माध्यम से तत्काल गैस कनेक्सन दिलाने का काम सुनिश्चित करें।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस लक्ष्य के साथ सभी अनुसूचित जनजाति , अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं वनाधिकारपट्टा हासिल किये लोगों को भी निशुल्क एलपीजी कनेक्सन दिये जाने का काम किया जाना है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गरीब माताओं-बहनों के आंसु पोछने और उनके चेहरे पर खुशी लाने के उद्देश्य से इस योजना की शुरूआत 2 अक्टूबर 2015 को झारखण्ड के दुमका से शुरू किया था। हमें हर हाल में यह लक्ष्य हासिल करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब बहनों के प्रति समर्पण के भाव से जज्बे और जुनून से सबके सहयोग से अभियान मोड में काम करके इस लक्ष्य पूरा करना है।

राज्य 20 सूत्री उपाध्यक्ष श्री राकेश प्रसाद ने कहा कि विकेन्द्रीकरण एवं सेवा भाव से इस लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। विकास आयुक्त श्री अमित खरे ने कहा कि खाद्य आपूर्ति विभाग ने ग्रामवार डाटा उपलब्ध कराया है जिससे लक्ष्य को पूरा करना आसान हो जाएगा। खाद्य आपूर्ति सचिव ने विस्तारपूर्वक योजना के कार्यान्वयन के बारे में बताया। योजना सह वित्त सचिव श्री सतेन्द्र सिंह ने सबका स्वागत करते हुए कहा कि अभियान मोड में समर्पित कार्य से ही परिणाम प्राप्त किये जा सकते है। मीडिया के सामने हुई खुली समीक्षा बैठक में राज्य भर से आये सभी जिला 20 सूत्री उपाध्यक्ष, प्रखण्ड उपाध्यक्ष तथा 20 सूत्री से जुड़े तमाम कर्मी उपस्थित थे।